

आज से।इसके अलावा, कड़ी निगरानी रखी जाएगी।यदि किसी अवैध खनन का पता चलता है, तो मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। किसी भी स्थिति में, विभिन्न खदानों के संबंध में स्थिति के बारे में विभाग द्वारा मुख्य सचिव को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जांच केवल प्रतिवादी संख्या 8 या 9 के आचरण तक ही सीमित नहीं होगी।यह सभी पट्टेदारों और विभाग के संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों के संचालन में होगी।केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच जल्द से जल्द, अधिमानतः छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(27) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। कोई लागत नहीं।

**आर.एन.आर**

**न्यायमूर्तिजी एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति निर्मल सिंह के समक्ष**

**आर. एस. डून,- याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़, चंडीगढ़ और अन्य- उत्तरदाता**

**सी.डब्ल्यू.पी. 2001 की संख्या 4692/सी**

**4 अप्रैल 2001**

**प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985-धारा 24-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति-यू.**

पी. एस. सी. चयन समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए-उन्हें चुनौती-न्यायाधिकरण ने बिना कोई कारण बताए एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करके चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी-चाहे वह धारा 24 के जनादेश का उल्लंघन हो-आयोजित, हाँ-एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करने से पहले, न्यायाधिकरण सभी घटकों पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जैसे कि अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन और सबसे बढ़कर, सार्वजनिक हित।

अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायाधिकरण द्वारा चयनित लोगों की नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए 1 जनवरी, 2001 के आदेश x का एक खाली पठन पारित किया गया। उम्मीदवार यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायाधिकरण ने कोई भी ऐसा कारण निर्दिष्ट नहीं किया है जो धारा 24 के मूल भाग में निहित बाधा का उल्लंघन करते हुए एकतरफा आदेश पारित करने की आवश्यकता के लिए दिमाग के उपयोग का संकेत दे। यह उस नुकसान से संबंधित मुद्दे से संबंधित नहीं है जो अंतरिम आदेश पारित नहीं होने पर आवेदक को उठाना पड़ सकता था। यह उस कारण के बारे में भी स्पष्ट रूप से चुप है जिसने न्यायाधिकरण को इस नियम से हटने के लिए प्रेरित किया कि रोक के लिए आवेदन की प्रतियां प्रभावित पक्ष को दी जानी चाहिए और अंतरिम रोक का आदेश पारित होने से पहले ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन है और केवल उसी आधार पर, इसे रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 11)

राजीव आत्मा राम और के. के. गुप्ता, याचिकाकर्ता की ओर से  
अधिवक्ता।

डॉ. बलराम के. गुप्ता, प्रत्यर्थी नं.2. की ओर से अधिवक्ता,

### निर्णय

न्यायमूर्तिजी जी. एस. सिंघवी,

(1) क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, अधिनियम) के तहत गठित एक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान के अधिदेश का पालन किए बिना एकतरफा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, यह मुख्य प्रश्न है जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ (जिसे इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में वर्णित किया गया है) द्वारा पारित 1 जनवरी, 2001 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर इन याचिकाओं में निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है-जिसके तहत उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा में याचिकाकर्ताओं और प्रोफार्मा प्रतिवादीगण की नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।

(2) रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 2 और प्रोफार्मा उत्तरदाता हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं।। दिसंबर, 2000 में उनके मामलों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 (संक्षेप में, 'विनियम') के तहत गठित चयन समिति द्वारा वर्ष 1998, 1999 और 2000 की रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय प्रशासनिक

सेवा में पदोन्नति के लिए विचार किया गया था चयन समिति की सिफारिशों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, लोक शिकायत और पेंशन (व्यक्तिगत और प्रशिक्षण विभाग) ने याचिकाकर्ताओं और प्रोफार्मा प्रतिवादीगण की नियुक्ति को अधिसूचित करने वाले विनियमों के विनियमन 7 (3) के तहत 3 जनवरी, 2001 को अधिसूचना जारी की। अगले दिन यानी 4 जनवरी, 2001 को भारत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 (इसके बाद '1954 नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 8 (1) के तहत एक और अधिसूचना जारी की, जिसे विनियमों के विनियम 9 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ *पढ़ा* गया, जिसके अनुसार चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया था।

(3) इस बीच, प्रतिवादी नंबर 2 ने चयन समिति के गठन और उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर सवाल उठाते हुए अधिनियम की धारा 19(1) के तहत एक आवेदन दायर किया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए भी आवेदन किया। 1 जनवरी, 2001 को न्यायाधिकरण ने प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ताओं और प्रोफार्मा प्रतिवादीगण की नियुक्तियों पर रोक लगा दी। गैर-आवेदनकर्ताओं में से छह (जिनमें से अधिकांश C.W.P. No. 4927- CAT of 2001 में याचिकाकर्ता हैं) ने एकतरफा स्थगन आदेश को हटाने के लिए 12 जनवरी, 2001 को न्यायाधिकरण के *समक्ष एक* विविध आवेदन दायर किया। इसे 2001 के M.A. No. 72 के रूप में पंजीकृत किया गया था। 3 दिनों के बाद, याचिकाकर्ता-आर. एस. दून ने 3 जनवरी, 2001 और 4 जनवरी, 2001 की अधिसूचनाओं की अभिलेख

प्रतियों को रखने के लिए 2001 की M.A. No. 73 दायर की। उन्होंने यह भी कहा कि इन अधिसूचनाओं के अनुसरण में, चयनित उम्मीदवार 22 जनवरी, 2001 को शामिल हुए हैं। 2001 का M.A. No. 108 हरियाणा सरकार की ओर से एकतरफा अंतरिम आदेश को हटाने के लिए इस आधार पर दायर किया गया था कि चयनित उम्मीदवारों ने 4 जनवरी, 2001 की अधिसूचनाओं के अनुसरण में ज्वइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अंतरिम आदेश के जारी रहने से आधिकारिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसी तरह, भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2001 और 4 जनवरी, 2001 की अधिसूचनाओं की प्रतियों को रिकॉर्ड में रखने के लिए 24 जनवरी, 2001 को एक विविध आवेदन दायर किया गया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि न्यायाधिकरण आगे की कार्रवाई के बारे में निर्देश दे सकता है। याचिकाकर्ताओं, भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित मामले का सामान्य तनाव यह था कि 1 जनवरी, 2001 के आदेश के संचार से पहले भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2001 और 4 जनवरी, 2001 की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं और चयनित उम्मीदवारों ने ज्वइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्तियों पर रोक सार्वजनिक हित और सेवा के हित के लिए अत्यधिक हानिकारक थी और यदि चयनित उम्मीदवारों को शुल्क लेने की अनुमति दी जाती है तो आवेदक (प्रतिवादी संख्या 2) को अपूरणीय क्षति नहीं होगी। आवेदक (प्रत्यर्थी सं 2) इनमें से कुछ आवेदनों का जवाब दाखिल किया जिसमें उन्होंने अंतरिम आदेश को जारी रखने का अनुरोध किया।

(4) रिट याचिका में, यह कहा गया है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, न्यायाधिकरण अंतरिम आदेश की छूट्टियों के लिए दायर आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहा है और भारत संघ और संघ लोक

सेवा आयोग (न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 और 2) द्वारा लिखित बयान दाखिल नहीं करने के बहाने मामले को समय-समय पर स्थगित किया जा रहा है और इस तरह, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदों का प्रभार लेने के उनके वैध अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने 2000 के एम.ए. क्रमांक 1345 (ओ.ए. 2000 की संख्या 874 **अभय सिंह बनाम भारत संघ और अन्य**) में पारित 13 दिसंबर, 2000 के आदेश का उल्लेख किया है।) और 2001 का ओ.ए. क्रम संख्या 209 **मोहन लाल कौशिक बनाम भारत संघ एवं अन्य** में 16 मार्च, 2001 का आदेश यह दर्शाने के लिए पारित किया गया कि चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को चुनौती देने वाले अन्य मामलों में, न्यायाधिकरण ने नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रासंगिक कारकों और धारा 24 के अधिदेश पर विचार किए बिना, उसने एकतरफा *अंतरिम आदेश* दिया, जिसे समय-समय पर जारी किया जा रहा है।

(5) इस स्तर पर, हम यह अवलोकन करना आवश्यक समझते हैं कि याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा दायर विभिन्न विविध आवेदनों को विधिवत पंजीकृत किया गया था और न्यायाधिकरण के समक्ष रखा गया था, लेकिन उसमें की गई प्रार्थना को स्वीकार किए बिना, न्यायाधिकरण ने मामले को अलग-अलग तिथियों पर स्थगित कर दिया है। यह स्पष्ट रूप से 2000 की ओ.ए. क्रम संख्या 1078 **नीलम पी. कासनी बनाम भारत संघ और अन्य** (अनुलग्नक पी13) की आदेश-पत्रों की टाइप की गई प्रतियों से स्पष्ट होता है। इन *आदेश-पत्रों* को पढ़ने से पता चलता है कि 1 जनवरी, 2001 को एकतरफा आदेश पारित करते समय न्यायाधिकरण ने अगली तारीख 16 जनवरी, 2001 निर्धारित की थी,

जिस तारीख को मामले को 12 फरवरी, 2001 तक के निर्देश के साथ स्थगित कर दिया गया था और कहा कि अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। 24 जनवरी, 2001 को 2001 के विविध आवेदन संख्या 108 की सूचना 12 फरवरी, 2001 के लिए दी गई थी। 30 जनवरी, 2001 को भारत सरकार की ओर से दायर विविध आवेदन को 12 फरवरी, 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 12 फरवरी, 2001 को मामले को 27 फरवरी, 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिस तारीख को आवेदक की ओर से दायर संशोधित O.A को रिकॉर्ड में लिया गया था। कुछ गैर-याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर लिखित बयानों को भी रिकॉर्ड में लिया गया और लिखित बयान दाखिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार के वकील द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए मामले को 16 मार्च, 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 16 मार्च, 2001 को मामले को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 12 फरवरी, 2001, 27 फरवरी, 2001 और 16 मार्च, 2001 को न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं, भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा अंतरिम रोक को हटाने के लिए दायर विविध आवेदनों पर कोई आदेश पारित नहीं किया और यही कारण है कि याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करके इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की है।

(6) श्री श्री राजीवी आत्मिया राम ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ताओं और प्रोफार्मा प्रतिवादीगण की नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए जनवरी, 2001 की तारीख को पारित आदेश को अवैध घोषित किया जाना चाहिए और रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम की धारा 24 के अधिदेश का उल्लंघन है। विद्वान वकील ने

इस तथ्य पर जोर दिया कि धारा 24 के परंतुक के संदर्भ में, न्यायाधिकरण को अनिश्चितकालीन स्थगन आदेश पारित करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है और तर्क दिया कि उसने बिना कोई कारण बताए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगाकर एक गंभीर अवैधता की है और इस तथ्य की अनदेखी की है कि यदि रिट याचिकाओं में आक्षेपित अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया होता तो आवेदक को कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक निवारक है और इसलिए, विवादित आदेश को रद्द किया जा सकता है और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया जा सकता है। डॉ. बलराम गुप्ता ने श्री राजीव आत्मा राम की दलीलों का विरोध किया और कहा कि इस न्यायालय को विवादित आदेश को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अनिवार्य रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया

कि न्यायाधिकरण ने चयन की प्रक्रिया में की गई गंभीर अवैधताओं के बारे में प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन में किए गए कथनों पर विधिवत विचार करने के बाद चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि मामला 16 अप्रैल, 2001 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है और इसलिए न्यायाधिकरण को प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन पर सुनवाई करने और अंत में निर्णय लेने का निर्देश देकर न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा।



(7) हमने संबंधित तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है।

(8) अधिनियम की धारा 24, जो अंतरिम आदेश देने के लिए शर्तें निर्धारित करती है, निम्नानुसार है:

“24. अंतरिम आदेश देने की शर्तें-इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी आवेदन पर या उससे संबंधित किसी भी आय में कोई अंतरिम आदेश (चाहे वह निषेधाज्ञा या रोक के रूप में हो या किसी अन्य तरीके से) तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(a) ऐसे अंतरिम आदेश के लिए याचिका के समर्थन में ऐसे आवेदन और सभी दस्तावेजों की प्रतियां उस पक्ष को प्रस्तुत की जाती हैं जिसके खिलाफ ऐसा आवेदन किया जाता है या किया जाना प्रस्तावित है; और

(b) ऐसे पक्ष को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाता है:

बशर्ते कि एक न्यायाधिकरण खंड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को समाप्त कर सकता है और एक असाधारण उपाय के रूप में एक अंतरिम आदेश दे सकता है, यदि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से यह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक को होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, जिसकी पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति धन में नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी अंतरिम आदेश,

यदि इसे जल्द ही खाली नहीं किया जाता है, तो उस तारीख से चौदह दिनों की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उक्त अपेक्षाओं का उस अवधि की समाप्ति से पहले पालन नहीं किया गया हो और -

न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश का संचालन जारी रखा है।”

(9) ऊपर उद्धृत प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि धारा 24 का मूल भाग एक गैर-अस्पष्ट उपवाक्य से शुरू होता है और इसमें न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश के अनुदान के खिलाफ एक रोक है, चाहे वह निषेधाज्ञा या रोक के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से, जब तक कि रोक के लिए आवेदन की प्रतियां और अंतरिम आदेश के लिए याचिका का समर्थन करने वाले दस्तावेज विरोधी पक्ष को प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं और ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है। धारा 24 का प्रावधान जो काफी हद तक संविधान के अनुच्छेद 226 (3) और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 के समान है, न्यायाधिकरण को प्रभावित पक्ष को स्थगन आवेदन की प्रति की आपूर्ति करने और ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकताओं को समाप्त करने का अधिकार देता है यदि यह संतुष्ट है कि लेकिन एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए, आवेदक को ऐसा नुकसान होगा जिसे धन के संदर्भ में पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग कई शर्तों के साथ किया जाता है और जब तक वे संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक न्यायाधिकरण एक एकतरफा अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता है। परंतुक में निहित

शर्तों में से एक यह है कि न्यायाधिकरण को स्थगन के लिए आवेदन की प्रति प्रदान किए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना अंतरिम आदेश नहीं देने के सामान्य नियम से विचलन करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए और ऐसे कारणों से यह पता चलना चाहिए कि *आवेदक को* होने वाले नुकसान की भरपाई धन के संदर्भ में पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती है। दूसरी शर्त यह है कि एकतरफा अंतरिम आदेश यदि पहले खाली नहीं किया गया है, तो यह उस तारीख से 14 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आवेदन की प्रतियां प्रभावित पक्ष को उस अवधि की समाप्ति से पहले नहीं दी गई हैं और न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश का संचालन जारी रखा है।

(10) उपरोक्त के आलोक में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा पारित 1 जनवरी, 2001 का आदेश धारा 24 और उसके परंतुक में सन्निहित शर्तों को पूरा करता है और क्या याचिकाकर्ताओं और कुछ प्रतिवादीगण द्वारा उसी की एक पक्षीय अंतरिम आदेश को निरस्त करने हेतु बिना पूर्व अंतरिम आदेश को जारी रखने का कोई औचित्य था। इस उद्देश्य के लिए, 1 जनवरी, 2001 के आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। वही नीचे लिखा है:

“मौजूद : श्री आर. के. शर्मा, आवेदक के वकील।

16 जनवरी, 2001 के लिए कारण बताने के लिए

सूचना।

इस बीच निजी प्रतिवादीगण की नियुक्तियों पर

रोक लगा दी गई है।

न्यायालय के अनुरोध पर, भारत संघ के वरिष्ठ स्थायी वकील श्री एच. सी. अरोड़ा प्रतिवादी नंबर 1 और 2 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

उत्तरदाता नंबर 3 से 14 के लिए प्रक्रिया दस्ती

जारी करे”

(11) ऊपर उद्धृत आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि न्यायाधिकरण ने ऐसा कोई भी कारण निर्धारित नहीं किया है जो धारा 24 के मूल भाग में निहित प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए *एकतरफा आदेश* पारित करने की आवश्यकता के प्रति विवेक के प्रयोग का संकेत दे। यह उस नुकसान से संबंधित मुद्दे से संबंधित नहीं है जो आवेदक (प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ) को भुगतना पड़ सकता है यदि अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था। यह उन कारणों के बारे में भी स्पष्ट रूप से मौन है जिन्होंने न्यायाधिकरण को इस नियम से हटने के लिए प्रेरित किया कि रोक के लिए आवेदन की प्रतियां प्रभावित पक्ष को दी जानी चाहिए और अंतरिम रोक का आदेश पारित होने से पहले ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन करता है और केवल उसी आधार पर इसे रद्द किया जा सकता है।

(12) हमारा आगे यह विचार है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक लगाने का कोई कानूनी या अन्यथा औचित्य नहीं था। उत्तरदाता नंबर 2 द्वारा धारा 19(1) के तहत दायर की गई आवेदन पर विचार केवल एक प्रथम दृष्टया मामला मामले की मौजूदगी की सुझाव दे सकता है।" *तथापि*, यह अपने आप में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था और हमारी सुविचारित राय में, इन याचिकाओं में आक्षेप किए गए आदेश की तरह, एक आदेश पारित करने से पहले, न्यायाधिकरण अन्य घटकों पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, जैसे कि अपूरणीय हानि, सुविधा का संतुलन और सबसे बढ़कर, सार्वजनिक हित। इस बात पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है कि चयन, नियुक्ति से संबंधित विवादों के निर्णय, पदोन्नति, वरिष्ठता आदि, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को, एक अंतरिम आदेश पारित करने के पहले से जुड़े मामलों में, सभी घटकों के अस्तित्व के बारे में खुद को *संतुष्ट करना* चाहिए, जैसे कि प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन और सबसे बढ़कर, सार्वजनिक हित।

(13) दिल्ली उच्च न्यायालय की रणबीर चंद्र बनाम भारत संघ और अन्य<sup>1</sup> डिवीजन बेंच ने आयकर आयुक्त के पद पर की गई नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले के संबंध में अंतरिम आदेश के विषय पर कानून की स्पष्ट व्याख्या की। डिवीजन बेंच ने अपरिवर्तनीय चोट और

<sup>1</sup> 1978 (2) एस.एल.आर.340

सुविधा के संतुलन के मुद्दे पर विचार करते हुए कहा:

### अनतिक्रिय चोट

आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका दाखिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई सीधी चोट, किसी अपूरणीय क्षति का तो बिल्कुल भी सबूत नहीं दिया जा सकता है। उक्त आदेश ने सरकार को अपीलार्थी को आयकर आयुक्त के पद पर नियुक्त करने में सक्षम बनाया। रिट याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों में से कोई भी इससे प्रभावित होगा या नहीं, इस पर संदेह है। आय-कर आयुक्त के पद पर पदोन्नति चयन और योग्यता के आधार पर होती है। अपीलार्थी की वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण का अर्थ यह नहीं है कि केवल वरिष्ठता में लाभ से अपीलार्थी आय-कर आयुक्त के रूप में नियुक्त होने का हकदार था। नियुक्ति केवल चयन द्वारा की जा सकती थी। यह ज्ञात नहीं है कि रिट याचिका दायर करने वाले कितने व्यक्तियों को आय-कर आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाएगा। वे केवल यह आग्रह कर सकते थे कि अपीलार्थी को उनसे वरिष्ठ बनाया जाए। हालाँकि, वे यह आग्रह नहीं कर सके कि चयन वरिष्ठता के आधार पर किया गया था। यह मानते हुए कि रिट याचिका दाखिल करने वाले कुछ व्यक्तियों को आयकर आयुक्त के रूप में भी चुना जाएगा और अपीलकर्ता के कनिष्ठ होंगे क्योंकि अपीलकर्ता की पिछली पदोन्नति आक्षेपित आदेश के आधार पर होगी, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आक्षेपित आदेश का परिणाम होगा। इसके विपरीत, यह चयन के लिए विचार किए जाने वाले अपीलार्थी की पात्रता का परिणाम होगा। यह योग्यता उन्हें न्याय के आधार पर दी गई थी। रिट याचिका पर विचार करने और

राहत देने में पहला सिद्धांत अन्याय का निवारण करना और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। तथ्य ऐसे हैं कि अपीलार्थी के साथ अन्याय किया गया था। इस तरह के अन्याय के निवारण का उद्देश्य दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। किसी भी तरह से, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह रिट याचिकाकर्ताओं के साथ कोई अन्याय करता है। अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की असाधारण शक्तियों का प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब न्याय की मांग होती है।"

### ***सुविधा का संतुलन***

सिविल सेवकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में यह सामान्य नियम है कि रिट याचिका के सफल होने पर सरकार की विवादित प्रशासनिक कार्रवाई को दरकिनार कर दिया जाता है। सुविधा का संतुलन सरकारी आदेश के संचालन को निलंबित नहीं करने के पक्ष में है। क्योंकि, व्यक्तिगत रिट याचिकाकर्ता को हमेशा उचित राहत दी जा सकती है यदि उसकी रिट याचिका सफल हो जाती है। सरकार कानून की सरकार है। यह हमेशा रिट याचिकाकर्ताओं को इस तरह की राहत देने वाले न्यायालयों के फैसलों को लागू करती है। लेकिन इस न्यायालय के लिए सरकारी आदेश के संचालन को केवल इसलिए रोकना बेहद असामान्य है क्योंकि रिट याचिका एक प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होती है। इस प्रकार की क्रिया के खिलाफ कई विचार हैं। चूंकि आम तौर पर सिविल सेवक के किसी विशेष मामले के तथ्यों में जाना सरकार और संघ लोक सेवा आयोग का कार्य होता है, इसलिए तथ्यों जांच और

ऐसे मामले में न्याय करने के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। सरकार के आदेश के खिलाफ स्थायी आदेश जारी करने का मुद्दा सरकार की कार्यक्षमता में रुकावट डालता है। इस तरह की बाधा को शुरू में टाला जाना चाहिए, जब तक कि यह अनिवार्य नहीं हो जाता है जब रिट याचिका का गुण-दोष के आधार पर निपटारा किया जाता है। प्रशासनिक कार्रवाई के संचालन पर समय से पहले रोक लगाने से तीसरे पक्ष के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके लिए कोई मुआवजा उपलब्ध नहीं हो सकता है या पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसलिए, यह केवल एक असाधारण मामला है कि सरकार के खिलाफ सिविल सेवक द्वारा एक रिट याचिका में रोक दी जाती है।”

(14) डॉ. नारायण बनाम आर. वैद्यनाथ और अन्य<sup>2</sup> में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में रीडर की नियुक्ति के खिलाफ पारित निषेधाज्ञा के आदेश को दरकिनारा करते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की:

मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि सुविधा का संतुलन प्रतिवादी 3 को विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में पाठक के पद का कार्यभार संभालने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी करने में कैसे निहित है। वह वादी को विस्थापित नहीं करने जा रहा है क्योंकि वादी उस पद पर

<sup>2</sup> AIR 1975 कर्नाटक 117



नहीं है। यदि वादी सफल होता है, तो प्रतिवादी 3 को पद खाली करना होगा और एक नई नियुक्ति करनी होगी। मुकदमेबाजी को अंततः समाप्त होने में कई साल लग सकते हैं। क्या कोई न्यायालय विश्वविद्यालय में एक पाठक के पद को निषेधाज्ञा का आदेश जारी करके खाली रखने और इस तरह छात्रों को पीड़ित करने के लिए उचित है? संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं में जहां सरकार, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती दी गई है, इस न्यायालय ने, मेरी जानकारी में, नियुक्त उम्मीदवारों को उन पदों का प्रभार संभालने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, जहां उन्हें नियुक्त किया गया था, जब तक कि यह ऐसा मामला न हो जहां इस तरह की नियुक्ति से याचिकाकर्ता को विस्थापित किया जाने वाला हो। यदि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए वादी द्वारा अनुरोध की गई प्रकृति का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगा, तो क्या एक अधीनस्थ अदालत संशोधन के तहत आदेश देने में सक्षम है?

यदि यह न्यायालय नीचे के न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो यह पार्टियों को राज्य सरकार या अन्य अधिकारियों द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती देते हुए अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा शुरू करने के लिए

प्रोत्साहित करेगा, और यदि अधीनस्थ न्यायालय अंधाधुंध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हैं तो प्रशासन लकवाग्रस्त हो सकता है।”

(15) हमारी राय में, भले ही उपर्युक्त दो मामलों में से पहले का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किया गया था और दूसरे मामले का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किया गया था, उसमें निर्धारित सिद्धांत काफी प्रासंगिक हैं और विवादित आदेश को रद्द करने के लिए हाथ में लिए गए मामले पर लागू होने के योग्य हैं क्योंकि न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 24 के परंतुक के जनादेश की अनदेखी करते हुए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक लगाकर गंभीर अवैधता की है और यह तथ्य कि आवेदक को कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत अधिक, अपूरणीय क्षति और सुविधा और सार्वजनिक हित का संतुलन स्पष्ट रूप से इस तरह के अंतरिम आदेश के पारित होने के खिलाफ था। जिस बात ने हमें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया है वह यह है कि याचिकाकर्ताओं और प्रोफार्मा प्रतिवादीगण के चयन को चुनौती देने वाले दो मामलों में, न्यायाधिकरण ने स्थगन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, लेकिन तीसरे मामले में, सभी नियुक्तियों पर इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना रोक लगा दी गई है कि इस तरह की रोक जनहित के लिए अत्यधिक हानिकारक होगी।

(16) हमारा यह भी मानना है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर किए गए मामलों में सुविधा का संतुलन हमेशा अंतरिम आदेश के

अनुदान के विरुद्ध होता है। यदि ट्रिब्यूनल को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर आवेदन की अनुमति देनी है, तो सबसे अच्छा, याचिकाकर्ताओं और प्रोफार्मा उत्तरदाताओं के चयन को नए चयन करने के उद्देश्य से एक समीक्षा चयन समिति बुलाने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाएगा।

उस स्तर पर, प्रतिवादी संख्या 2 का चयन हो भी सकता है और नहीं भी। यदि उसका चयन और नियुक्ति हो जाती है, तो पदोन्नति और परिणामी राहत देने के उसके दावे पर विचार करना संभव हो सकता है। हालाँकि, यदि आवेदन अंततः खारिज कर दिया जाता है, तो ट्रिब्यूनल के लिए चयनित उम्मीदवारों की पूर्वव्यापी नियुक्तियों का निर्देश देना या आधिकारिक उत्तरदाताओं को उन्हें उस अवधि के लिए वेतन देने का निर्देश देना संभव नहीं होगा, जब उन्हें सदस्य के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा. उस अवधि के लिए वेतन जो उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया गया था। इस प्रकार, न्यायाधिकरण चुनौती के तहत आदेश पारित करने में बिल्कुल भी उचित नहीं था।

(17) ऊपर बताए गए कारणों से, 2001 सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4927-सीएटी अनुमति है। न्यायाधिकरण द्वारा पास किए गए 1 जनवरी 2001 के आदेश को रद्द किया जाता है, जो 16 जनवरी 2001 तक आगे बढ़ा, उस प्राथमिक दिशा में कि 1 जनवरी 2001 के बाद जारी किए गए अधिसूचनाएँ, और आगे जारी किए जाने वाले आदेश पर प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य समान अवस्थित व्यक्तियों द्वारा दी गई आवेदन के अंतिम

न्यायिक निर्णय के प्रति विषय रहेंगे।"

(18) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1 जनवरी, 2001 के आदेश को रद्द कर दिया गया है, अन्य दो याचिकाओं यानी 2001 सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4927-सीएटी और 2001 की 4928- सीएटी का निष्फल के रूप में निपटारा किया जाता है।

**आर.एन.आर**

**अस्वीकरण** : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

3 LO

I.L.R. Punjab and Haryana

2001(2)

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा